जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 43 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 4 सितम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

# द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार की अस्सीवीं सालगिरह पर, चीन द्वारा अति प्रभावशाली परेड आयोजित

## परेड की सलामी लेते वक्त राष्ट्रपति शी के एक तरफ पुतिन व दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग थे

**- डॉ. सतीश मिश्रा -**

**- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -**

- **इस भव्य परेड में भारत भी आमंत्रित था या नहीं यह तो दृढ़ता से कहना मुश्किल है, क्योंकि, भारत के विदेश मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि प्र.मंत्री ने स्वयम् यह निर्णय लिया था कि भारत इस विजय समारोह में शामिल नहीं होगा।**
- **इस प्रभावशाली परेड समारोह ने यह साबित कर दिया कि, कूटनीति की दृष्टि से बीजिंग ने उभरती इकॉनमीज़ व ग्लोबल साऊथ क्षेत्र में अपनी अच्छी व मजबूत पैठ व पकड़ बनाई है।**
- **तियानमन स्क्वायर पर आयोजित इस परेड को सम्बोधित करते हुए, चीन के राष्ट्रपति शी ने कहा, विश्व आज दोराहे पर खड़ा है, तथा ये ही विकल्प हैः शांति या युद्ध, संवाद या खुला सामना 'विन-विन या ज़ीरो -सम गेम' तथा चीन इतिहास के प्रवाह के साथ है, तथा चीन की विकास की यात्रा अब नहीं रुकेगी।**

नई दिल्ली, 3 सितंबर। अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, चीन ने आज अपनी अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की। इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मौजूदगी ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि बीजिंग अब पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार है - यह संदेश खास तौर पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को दिया गया है।

यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित की गई, जिसे पश्चिमी देशों के नेताओं ने सतर्कता और संदेह की दृष्टि से देखा।

असल में, चीन का यह शक्ति-प्रदर्शन अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था को तोड़ने की नीति और अंतरराष्ट्रीय समझौतों व संस्थाओं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन को कमज़ोर करने की पृष्ठभूमि में देखी जानी चाहिए।

अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत द्वारा 2021 में बनाए गए क्वॉड्रिलेटरल सिक्युरिटी डायलॉग्स (क्वाड) को बीजिंग ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने की कोशिश के रूप में देखा। अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और जापान के नेता इस कार्यक्रम से अनुपस्थित रहे और दक्षिण कोरिया व सिंगापुर जैसे देशों ने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। हालांकि, शी जिनपिंग की गैस्ट लिस्ट ने ग्लोबल साउथ और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर चीन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाया। यह स्पष्ट नहीं है कि परेड़ के लिए भारत को आमंत्रित किया गया था या नहीं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोच समझ कर इस कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला लिया। भारत आज के सैन्य परेड में शामिल नहीं था।

तियानआनमेन स्क्वायर में लगभग 50,000 दर्शकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति शी ने कहा कि मानवता एक मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे "शांति या युद्ध, संवाद या टकराव, दोनों की जीत कोई एक जीते दूसरा हारे जीत या शून्य-राशि में से चयन करना है।

उन्होंने कहा कि चीनी लोग "इतिहास के सही पक्ष पर खड़े हैं" और चीनी राष्ट्र का पुनरुत्थान रोका नहीं जा सकता।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# ब्यावर विधायक की पुत्री पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर नियुक्ति लेने का आरोप

भीलवाड़ा, 3 सितम्बर (निसं)। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा उपखंड मुख्यालय पर तैनात कार्यवाहक तहसीलदार और ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर राजकीय सेवा लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

- **अतिरिक्त निदेशक विशेष योग्यजन ने राजस्व बोर्ड रजिस्ट्रार को कार्यवाही करने के लिये लिखा।**

करेड़ा तहसीलदार कंचन चौहान ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की पुत्री हैं। उन पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति लेने का आरोप है। फिलहाल वे कार्यवाहक तहसीलदार करेड़ा पद नियुक्त है। शिकायत के चलते निदेशालय विशेष योग्यजन के अतिरिक्त निदेशक चन्द्रशेखर चौधरी ने राजस्व बोर्ड अजमेर के रजिस्ट्रार को प्रकरण में कार्रवाई कर निदेशालय को जानकारी भिजवाने को कहा है। आरोप है कि कंचन चौहान ने सितंबर 2024 को कार्यवाहक करेड़ा तहसीलदार के पद पर ज्वाइन किया था। उन्होंने बधिर

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# दूसरे दिन भी विधानसभा में भाजपा-कांग्रेस टकराव, कार्यवाही स्थगित हुई

## कांग्रेस ने झालावाड़ स्कूल हादसे को मुद्दा बनाया, भाजपा ने "महिला विरोधी राहुल गांधी" नारा लगाया

**-विधानसभा संवाददाता-**

- **विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही।**

जयपुर, 3 सितम्बर। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, झालावाड़ स्कूल हादसे और सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सदन के भीतर और बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने हाथों में, "शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो," लिखी तख्तियां ले रखी थीं और बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी हुई थीं। साथ ही, झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा और मोमबत्तियां जलाकर संवेदना प्रकट की।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने हादसे के शिकार बच्चों को न केवल नज़रअंदाज किया, बल्कि विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। टीकाराम जूली ने घोषणा की कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस हादसे में मृत सातों बच्चों के नाम पर 7 संभागों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे।

इस विरोध प्रदर्शन में ए.आई.सी.सी. महासचिव, पूर्व डिप्टी सीएम एवं टोंक विधायक सचिन पायलट और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय रही।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्कूलों में लगातार हो रहे हादसों में अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिख रही। स्कूलों की हालत जर्जर है, फंड की भारी कमी है और स्कॉलरशिप तक रोकी जा रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि वीर बालिका कालीबाई भील को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, राजीव गांधी एक्सलैंस स्कॉलरशिप की संख्या घटा दी गई है और ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं कि छात्रों को इसका लाभ ही न मिल सके।

जूली ने कहा, "बच्चों की मौत पर सरकार का रवैया शर्मनाक है। ये बच्चे राजस्थान के हैं, अमेरिका के नहीं, जिन्हें श्रद्धांजलि देने में भी सरकार को संकोच हो रहा है। कांग्रेस ने आईफा और भारत मंडपम जैसे आयोजनों पर खर्च को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि जब आयोजनों के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं, तो आखिर स्कूलों की मरम्मत और बच्चों की सुरक्षा के लिए बजट क्यों नहीं है?

वहीं, सदन के अंदर भी कांग्रेस विधायकों ने झालवाड़ स्कूल हादसे को लेकर शून्यकाल में विरोध जताया। कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने हादसे का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस के हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने "महिला विरोधी राहुल गांधी" का नारा लगाया, जिसे अन्य भाजपा विधायकों ने भी दोहराया। इससे सदन का माहौल और ज्यादा गरमा गया।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# 'एक राज्य में दोहरी सत्ता ( राज्यपाल और राज्य सरकार ) नहीं हो सकती'

## सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सातवें दिन की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा

**-जाल खंबाता-**

**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

- **विपक्ष शासित राज्यों ने विधेयकों को रोक लेने के राज्यपाल के अधिकार के विरूद्ध दलीलें दीं और कहा, कानून बनाना विधानसभा का काम है राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं है।**
- **सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिलों पर एक्शन लेने के लिए राज्यपाल पर समय सीमा लागू करने पर राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए रैफरैंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।**

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। राष्ट्रपति - संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के सातवें दिन बुधवार को तीन विपक्ष-शासित राज्यों ने दलील दी कि राज्यपाल को बिल रोक कर रखने का विवेकाधिकार नहीं है, क्योंकि कानून बनाने का काम विधानमंडल का है और इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती।

पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार (3 सितम्बर 2025) को राष्ट्रपति- संदर्भ पर सुनवाई जारी रखी। इस संदर्भ में सवाल यह है कि क्या अदालतें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकती हैं कि वे विधानसभा से पारित विधेयकों पर कितने समय के अन्दर निर्णय ले लें।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि राज्यपाल बिलों पर अनिश्चितकाल तक कुंडली मारकर बैठे नहीं रह सकते।

पश्चिम बंगाल की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जो बिल राज्यपाल को भेजा जाता है, उसे उस पर मंजूरी देनी होती है। केन्द्र सरकार चाहे तो किसी राज्य कानून को रद्द कर सकती है या फिर उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जनता की इच्छा का सम्मान होना ही चाहिए।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# एन. डी. ए. का बिहार बंद आज

पटना, 03 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के महिला मोर्चा ने चार सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है।

यह बंद गुरुवार चार सितंबर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। चार सितंबर को भाजपा समेत राजग के सहयोगी दलों के नेता सड़कों पर उतरेंगे। इस मामले पर भाजपा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग कर रही है।

- **प्रधानमंत्री की मां को कहे गए अपशब्दों के विरोध में बंद आहूत किया गया है।**

बिहार भाजपा की ओर से बंद का नेतृत्व कर रहे पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष और सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां के लिये अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिहार

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# कैंसर की दवाएं, पनीर ब्रेड, मक्खन, पास्ता के दाम घटने की संभावना

## छोटी कारों, बाइक, होटल में ठहरने और फिल्म टिकटों की दरों में भी राहत मिल सकती है

**-जाल खंबाता-**

**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**

- **जीएसटी काउन्सिल दो दिवसीय बैठक में टैक्स स्लैब्स को तर्क संगत बनाने पर गंभीर चर्चा की गई। फिलहाल चार स्लैब हैं, 5 प्रतिशत, 12,18 और 28 प्रतिशत। अब दो ही स्लैब करने की सिफारिशों पर विचार चल रहा है, अगर ऐसा होता है तो जनता व व्यापारी वर्ग को भारी राहत मिलेगी।**
- **सरकार की योजना है कि 28 प्रतिशत टैक्स की श्रेणी में आने वाले 90 प्रतिशत सामान को 18 प्रतिशत में लाया जाएगा और 12 प्रतिशत टैक्स वाले सामान को 5 प्रतिशत में शामिल किया जाएगा।**
- **सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव से 50,000 करोड़ रु. का नुकसान होगा पर खपत बढ़ने से इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी।**

नई दिल्ली, 3 सितंबर। गुड्स एण्ड सर्विसेज़ (जीएसटी) काउन्सिल ने बुधवार को यहां अपनी दो दिवसीय बैठक के पहले दिन व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ (बर्डन ऑफ कम्प्लायंस) कम करने के लिए कई फैसले किए। जिन उपायों को मंजूरी दी गई उनमें एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्ट-अप्स के लिए पंजीकरण का समय 30 दिन से घटाकर केवल तीन दिन करना शामिल है। निर्यातकों के लिए स्वचालित जीएसटी रिफंड (ऑटोमेटेड जी.एस.टी. रीफण्ड) का प्रस्ताव भी पास किया गया।

काउन्सिल ने बुधवार सुबह अपनी बैठक की शुरुआत जीएसटी टैक्स स्लैब्स को तर्कसंगत बनाने के बड़े एजेंडे के साथ की। काउन्सिल मौजूदा टैक्स ब्रैकेट्स को आधा करने की सिफारिशों पर विचार कर रही है। फिलहाल व्यवस्था में चार स्लैब हैं - 5,12,18 और 28 प्रतिशत।

सरकार के फैसले से जिन क्षेत्रों को फायदा हो सकता है उनमें प्रमुख हैं-

ऑटोमोबाइल्सः 1200 सीसी तक की छोटी कारें, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो सकता है।

हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजनः होटल में ठहरने और फ़िल्म टिकटों पर दरें 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो सकती हैं।

स्वास्थ्य सेवाएंः कैंसर की दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है। अन्य दवाओं और ज़रूरी मेडिकल सामान को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा को भी कर-मुक्त करने की संभावना है।

दैनिक उपयोग की वस्तुएँः पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा, फलों का रस, नारियल पानी, मक्खन, चीज़, पास्ता

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# उपराष्ट्रपति चुनाव की "मॉक ड्रिल"

नयी दिल्ली, 03 सितंबर। इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नए सांसदों को मॉक पोल के जरिए मतदान प्रक्रिया समझाने की योजना बना रहा है, ताकि सांसदों को मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक दिन पहले आठ सितंबर को इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली में बैठक करेंगे। इस दौरान उन्हें मतदान प्रक्रिया समझायी जायेगी और एक 'मॉक पोल' भी कराया जाएगा। इसके जरिये विपक्ष के सांसदों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी, ताकि वे मतदान में किसी प्रकार की त्रुटि न करें।

- **इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए मतदान की "मॉक ड्रिल" करवाएगा।**

गौरतलब, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# 'विचलित मत हों यह केवल एक परेड है,' पुतिन ने कुढ़ते हुए अमेरिका को सलाह दी

## चीन के विशाल व आधुनिक हथियारों को देखकर ट्रंप ने कुढ़ते हुए कहा, जो देश एस.सी.ओ. सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं, उनका ध्येय अमेरिका के खिलाफ साजिश करना है

**- अंजन रॉय -**

**- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -**

- **पर यह भी सच है कि, चीन द्वारा परेड में प्रदर्शित सभी हथियार, चीन में ही निर्मित थे, और अब चीन के "इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर" की क्षमता अमेरिका के औद्योगिक आधारभूत ढांचे से किसी भी तरह कम नहीं है।**
- **अस्सी साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की जीत का आधार उसकी आधुनिक फैक्टरियों का जाल था, जो बिना किसी हिचकिचाहट व रुकावट के एलाइड फोर्सेज़ को लगातार हथियार, ट्रक, टैंक आदि सप्लाई करता रहा, जबकि जर्मनी का यह "इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस", एलाइड फोर्सेज़ ने काफी कुछ नष्ट कर दिया था।**
- **हथियारों के बारे में रिसर्च एण्ड डवलपमैंट" की दृष्टि से चीन अब अमेरिका से आगे नहीं, तो बराबर तो खड़ा ही है।**

नई दिल्ली, 3 सितम्बर। यह अपने आप में एक विरोधाभास था। बीजिंग की एक सड़क, जिसे एवेन्यू ऑफ़ एटर्नल पीस कहा जाता है, पर चीन ने हथियारों और गोला-बारूद का विशाल भंडार प्रदर्शित किया। आज हई इस परेड में दिखाई गई बीजिंग की सैन्य शक्ति ने पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि सबसे ताक़तवर अमेरिका को भी चिंतित कर दिया है।

गुस्से में आकर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मौके पर इकट्ठा हुए तीन नेता अमेरिका के खिलाफ़ साज़िश कर रहे हैं। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को जवाब दिया-आराम से रहो, यह सिर्फ़ एक परेड है।

लेकिन यह केवल परेड़ नहीं है। भारत को गंभीरता से नोटिस लेना चाहिए कि बीजिंग में आयोजित इस स्मृति कार्यक्रम में चीन ने क्या दिखाया। वहाँ चीनी राष्ट्रपति के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन भी मौजूद थे। चीन द्वारा दिखाए गए सभी सैन्य उपकरण और हथियार सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चीनी तकनीक और औद्योगिक क्षमता से बने थे पूर्णतया चीन निर्मित थे।

उनकी जबरदस्त मारक क्षमता ने यह साबित कर दिया कि चीन के पास मज़बूत औद्योगिक ढांचा और अनुसंधान-विकास की बुनियाद है। कुछ हथियार प्रणालियाँ इतनी उन्नत थीं कि अधिकांश सैन्य विशेषज्ञों ने माना कि वे अपने प्रतिद्वंदियों यहाँ तक कि अमेरिका से भी कहीं आगे हैं।

सिर्फ़ हथियारों का प्रदर्शन असली सैन्य शक्ति का प्रमाण नहीं होता, असली ताक़त हथियार बनाने की क्षमता से आती है। यह अमेरिका का औद्योगिक ढांचा था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध खत्म किया, न कि जर्मनी की विनिर्माण क्षमता के विनाश ने।

यह प्रदर्शन कम से कम यह तो दिखाता है कि चीन सैन्य उपकरणों के उत्पादन में अमेरिका की औद्योगिक और विनिर्माण क्षमता के क़रीब पहुँच रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि नौसैनिक शक्ति के मामले में चीन के पास जहाज़ों और अन्य जलपोतों की संख्या अमेरिका से 48 प्रतिशत अधिक है। थलसेना में भी चीन बड़ी है और कई क्षेत्रों में उसने अपनी सेना की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रणालियाँ विकसित कर ली हैं।

मिसाइलों के मामले में चीन ने अपना नवीनतम हथियार पेश किया- एक विशालकाय अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे आठ पहियों वाले ट्रक पर रखा गया था।

चीन के पास उपलब्ध नई हथियार प्रणालियाँ और तकनीकों ने सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। उसने लेज़र तकनीक भी विकसित कर ली है, जो दुश्मन पर उच्च शक्ति वाली लेज़र

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की

जयपुर, 3 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों की राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा को अपने एक वर्ष के कार्यकाल के आलोक में प्रकाशित पुस्तक "अभ्युदय की ओर" की प्रति भी भेंट की।

- **मुख्यमंत्री ने उन्हें "अभ्युदय की ओर" पुस्तक भेंट की।**